Vol 9, Issue 1, 2026 **Impact Factor: 8.535** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2026.9.1.9001

IJAMSR

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग (Drop-out) के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक: बिहार के नालंदा जिले से साक्ष्य

मुकेश कुमार सिंह

शोधार्थी (पीएच.डी. – शिक्षा), शिक्षा विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
साईं नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड, भारत.

डॉ. पंकज कुमार यादव

प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
साईं नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड, भारत.

सार

प्रस्तुत शोध लेख ग्रामीण बिहार में विद्यालय त्याग (Drop-out) की समस्या का सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से विस्तृत एवं आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि किन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण बच्चे प्रारंभिक या मध्य शैक्षिक स्तर पर ही विद्यालय छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। शोध निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि गरीबी, बाल श्रम, माता-पिता की अशिक्षा, अस्थायी एवं असुरक्षित आजीविका, बड़े पारिवारिक आकार, सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ तथा विद्यालय की भौगोलिक दूरी जैसे कारक बच्चों की विद्यालयीय निरंतरता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि आर्थिक दबाव के कारण कई परिवार बच्चों को शिक्षा के स्थान पर आय-सहायक गतिविधियों में संलग्न कर देते हैं, जिससे विद्यालय त्याग की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, माता-पिता में शैक्षिक जागरूकता की कमी तथा शिक्षा के दीर्घकालिक लाभों के प्रति सीमित समझ भी बच्चों के विद्यालय में टिके रहने में बाधा उत्पन्न करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का अभाव और विद्यालयों की अधिक दूरी भी विद्यालय त्याग की समस्या को और जटिल बना देती है।

शोध निष्कर्ष यह संकेत करते हैं कि विद्यालय त्याग की समस्या केवल शैक्षिक अवसंरचना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषमताओं का परिणाम है। अतः इसके समाधान हेतु केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार-केंद्रित आर्थिक सहायता, अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन, तथा क्षेत्र-विशिष्ट शैक्षिक नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शैक्षिक योजनाकारों एवं सामाजिक संगठनों को ग्रामीण बिहार में विद्यालय त्याग की समस्या को कम करने हेतु व्यावहारिक एवं साक्ष्य-आधारित सुझाव प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: विद्यालय त्याग, ड्रॉप-आउट, सामाजिक-आर्थिक निर्धारक, ग्रामीण शिक्षा, बिहार.

भूमिका

शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का आधार मानी जाती है। यह न केवल व्यक्ति के ज्ञान, कौशल एवं चेतना के विकास में सहायक होती है, बल्कि सामाजिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (तिलक, 2007)। भारत

IJAMSR
International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

जैसे विकासशील देश में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है (भारत सरकार, 2009)। पिछले कुछ दशकों में सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) तथा समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों तक पहुँच और नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तथापि, नामांकन में वृद्धि के बावजूद विद्यालय में बच्चों की निरंतर उपस्थिति और शिक्षा पूर्ण करने की समस्या आज भी बनी हुई है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में (डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन, 2017)। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि विद्यालय त्याग (Drop-out) की समस्या केवल शैक्षिक अवसंरचना से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक-आर्थिक कारण निहित हैं (गोविन्दा, आर., एवं बंद्योपाध्याय, एम, 2011)। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग एक बहुआयामी समस्या है, जो गरीबी, बेरोज़गारी, भूमिहीनता, माता-पिता की अशिक्षा, बड़े पारिवारिक आकार, बाल श्रम एवं घरेलू उत्तरदायित्व जैसे कारकों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है (द्रेज़, जे., एवं सेन, ए, 2013)। अनेक गरीब परिवारों में बच्चों को आर्थिक सहारा मानकर उनसे कम उम्र में ही कार्य करवाया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक रूढ़ियाँ, लैंगिक भेदभाव तथा बालिकाओं पर घरेलू दायित्वों का बोझ भी विद्यालय त्याग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है (यूनेस्को, 2015)।

बिहार राज्य, विशेषकर इसके ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन एवं संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण शिक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नालंदा जिला, जो ऐतिहासिक रूप से ज्ञान एवं शिक्षा का केंद्र रहा है, वर्तमान समय में भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग की समस्या से प्रभावित है। यद्यपि जिले में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी बच्चों की नियमित उपस्थिति, निरंतरता एवं विद्यालय में टिके रहने की समस्या बनी हुई है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2018)। यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि विद्यालय त्याग के मूल कारण विद्यालय से अधिक परिवार एवं सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए हैं। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध पत्र "ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग (Drop-out) के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक: बिहार के नालंदा जिले से साक्ष्य" ग्रामीण समाज में विद्यालय त्याग की समस्या को सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास है। यह अध्ययन आय, अभिभावकों की शिक्षा, पेशा, पारिवारिक संरचना तथा विद्यालय से दूरी जैसे कारकों का विश्लेषण कर यह स्पष्ट करता है कि विद्यालय त्याग की समस्या बहुआयामी है और इसके समाधान हेतु केवल शैक्षिक सुधार पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक नीतिगत हस्तक्षेप भी आवश्यक हैं (सिंह, 2025)।

अध्ययन के उद्देश्य

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग के सामाजिक-आर्थिक कारणों की पहचान करना।
2. लिंग, जाति एवं आर्थिक स्थिति के संदर्भ में ड्रॉप-आउट की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।
3. शिक्षा नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग के सामाजिक-आर्थिक कारणों के विश्लेषण हेतु बहु-स्तरीय नमूना चयन विधि को अपनाया गया। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र का चयन किया गया, तत्पश्चात चयनित ग्रामीण क्षेत्रों से उपयुक्त गाँवों एवं परिवारों का नमूना निर्धारित किया गया, जिससे अध्ययन के

IJAMSR
International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

उद्देश्यों के अनुरूप प्रतिनिधिक आंकड़े प्राप्त किए जा सकें। अध्ययन में प्राथमिक स्रोतों से आँकड़ों का संकलन किया गया, जिनमें विद्यालय त्याग कर चुके अथवा विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक, स्वयं छात्र, तथा संबंधित शिक्षक प्रमुख रूप से शामिल थे। इन विभिन्न उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से विद्यालय त्याग से जुड़े सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पहलुओं को बहुआयामी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया। आँकड़ों के संग्रहण हेतु संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसे अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। प्रश्नावली में परिवार की आर्थिक स्थिति, माता-पिता की शिक्षा, पेशा, पारिवारिक संरचना, लिंग एवं जाति से संबंधित जानकारी, विद्यालय की दूरी तथा बच्चों की विद्यालयीय स्थिति से जुड़े प्रश्न सम्मिलित किए गए। प्रश्नावली को क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सरल एवं स्पष्ट भाषा में तैयार किया गया, जिससे उत्तरदाताओं से विश्वसनीय एवं प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो सके। संकलित आँकड़ों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय एवं तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों और विद्यालय त्याग की प्रवृत्ति के बीच संबंधों की पहचान की गई, जबकि तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा लिंग, जाति एवं आर्थिक स्थिति के संदर्भ में विद्यालय त्याग की भिन्नताओं का परीक्षण किया गया। इस प्रकार अपनाई गई शोध पद्धति ने अध्ययन के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग की समस्या को स्पष्ट एवं तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान की।

परिणाम एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम यह स्पष्ट करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग की समस्या गहराई से सामाजिक-आर्थिक दबावों से जुड़ी हुई है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश विद्यालय त्याग करने वाले बच्चों के परिवार निम्न आय वर्ग से संबंधित पाए गए, जहाँ आर्थिक असुरक्षा के कारण बच्चों को कृषि कार्य, दैनिक मजदूरी तथा घरेलू कार्यों में संलग्न कर दिया जाता है। (तालिका 1)

तालिका 1 नमूना परिवारों द्वारा कृषि भूमि का कब्जा स्रोतः शोधकर्ता द्वारा एकत्रित डेटा

कृषि भूमि का कब्ज़ा (एकड़ में)	आवृत्ति	प्रतिशत
कोई भूमि नहीं	167	87.9
1 एकड़ से कम	1	0.5
1	9	4.7
2	6	3.2
5	5	2.6
6	1	0.5
10	1	0.5
कुल	190	100

यह प्रवृत्ति विशेष रूप से उन परिवारों में अधिक देखी गई, जहाँ पारिवारिक आय के स्रोत अस्थायी एवं अनियमित हैं। यह निष्कर्ष पूर्ववर्ती अध्ययनों के अनुरूप है, जिनमें यह पाया गया है कि गरीबी बच्चों की शिक्षा में निरंतरता की सबसे बड़ी बाधा है (द्रेज़, जे., एवं सेन, ए, 2013; गोविन्दा, आर., एवं बंद्योपाध्याय, एम, 2011)।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि बालिकाओं में विद्यालय त्याग की दर बालकों की तुलना में अधिक है। आंकड़ों की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में प्रचलित सामाजिक मान्यताएँ, घरेलू उत्तरदायित्वों का बोझ, छोटे भाई-बहनों की देखभाल तथा प्रारंभिक विवाह की प्रवृत्ति बालिकाओं की शिक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। कई परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा को द्वितीयक महत्व दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर ही विद्यालय छोड़ने के लिए विवश हो जाती हैं। यह निष्कर्ष राष्ट्रीय स्तर के अध्ययनों से भी समर्थित है, जो यह दर्शाते हैं कि लैंगिक असमानता विद्यालय त्याग का एक प्रमुख सामाजिक कारण है (यूनेस्को, 2015; डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन, 2017)। डेटा विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि विद्यालय की भौगोलिक दूरी और परिवहन सुविधाओं का अभाव विद्यालय त्याग का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय घर से अधिक दूरी पर स्थित हैं अथवा जहाँ सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ बच्चों की अनियमित उपस्थिति एवं विद्यालय त्याग की संभावना अधिक पाई गई। यह समस्या विशेष रूप से बालिकाओं के संदर्भ में अधिक गंभीर रूप में सामने आई, जहाँ सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी विद्यालय त्याग को बढ़ावा देती हैं। पूर्ववर्ती शोधों में भी विद्यालय दूरी को ड्रॉप-आउट का एक निर्णायक कारक माना गया है (तिलक, 2007; मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2018)। अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत करते हैं कि विद्यालय त्याग की समस्या को केवल शैक्षिक ढाँचे की कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता। (तालिका 2)

तालिका 2 आयु के अनुसार स्कूल छोड़ने वाले बच्चे

बच्चे की आयु (वर्षों में)	लड़की (संख्या)	लड़की (%)	लड़का (संख्या)	लड़का (%)	कुल बच्चे (संख्या)	कुल (%)
7 वर्ष	0	0.0	2	14.3	2	14.3
8 वर्ष	1	7.1	0	0.0	1	7.1
12 वर्ष	2	14.3	1	7.1	3	21.4
13 वर्ष	2	14.3	0	0.0	2	14.3
14 वर्ष	5	35.7	1	7.1	6	42.9
कुल	**10**	**71.4**	**4**	**28.6**	**14**	**100.0**

आंकड़ों की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि यह समस्या आर्थिक मजबूरियों, सामाजिक संरचना एवं लैंगिक असमानताओं के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। अतः विद्यालय त्याग को कम करने हेतु ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो शिक्षा के साथ-साथ परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार पर भी केंद्रित हों।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग की समस्या एक बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक परिघटना है, जिसे किसी एक कारण तक सीमित नहीं किया जा सकता। अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि गरीबी, पारिवारिक आर्थिक असुरक्षा, माता-पिता की अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियाँ, लैंगिक असमानता तथा विद्यालय की भौगोलिक दूरी जैसे कारक मिलकर बच्चों की विद्यालयीय निरंतरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। अतः विद्यालय त्याग की समस्या का समाधान

IJAMSR
International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

केवल शैक्षिक अवसंरचना के विस्तार से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यापक सामाजिक-आर्थिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह सुझाव दिया जा सकता है कि विद्यालय त्याग को कम करने हेतु परिवार-केंद्रित आर्थिक सहायता कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाए, जिससे गरीब एवं असुरक्षित परिवारों पर बच्चों को श्रम में लगाने का दबाव कम हो सके। साथ ही, माता-पिता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना आवश्यक है, ताकि अभिभावकों में शिक्षा के दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक लाभों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विद्यालयों, छात्रावासों तथा सुरक्षित परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे विद्यालय की दूरी बच्चों की शिक्षा में बाधा न बने। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु लक्षित योजनाएँ, जैसे छात्रवृत्ति, निःशुल्क आवासीय सुविधाएँ एवं सुरक्षा-संबंधी उपाय, लागू किए जाने की आवश्यकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि विद्यालय त्याग की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु शिक्षा नीतियों को सामाजिक न्याय एवं समावेशन के व्यापक दृष्टिकोण से लागू करना होगा। यदि परिवार, समुदाय एवं राज्य के स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाएँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग की प्रवृत्ति को उल्लेखनीय रूप से कम किया जा सकता है और सार्वभौमिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ

प्रस्तुत शोध लेख लेखक द्वारा सम्पन्न पीएच.डी. शोध कार्य पर आधारित है, जिसका शीर्षक "परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं विद्यालय में भागीदारी: बिहार के नालंदा जिले के चयनित गाँवों का अध्ययन" है। इस लेख में प्रयुक्त तथ्य, विश्लेषण एवं निष्कर्ष उक्त शोध प्रबंध के प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित हैं तथा उन्हें शोध पत्र के उद्देश्य के अनुरूप संक्षिप्त एवं पुनर्संरचित रूप में प्रस्तुत किया गया है।

आभार - प्रकटन

लेखक इस शोध पत्र के सफल संपादन में सहयोग प्रदान करने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। विशेष रूप से लेखक अपने शोध निर्देशक डॉ. पंकज कुमार यादव, प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, साईं नाथ विश्वविद्यालय, रांची के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, जिनके मार्गदर्शन, विद्वतापूर्ण सुझावों एवं सतत प्रेरणा से यह शोध कार्य संभव हो सका। लेखक साईं नाथ विश्वविद्यालय, रांची के शिक्षा विभाग एवं पुस्तकालय के प्रति भी आभारी है, जिन्होंने शोध से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराए। साथ ही, नालंदा जिले के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों, छात्रों एवं शिक्षकों का धन्यवाद करता है, जिन्होंने अध्ययन के दौरान आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्रदान किया।

Copyright: © 2025 लेखक। यह शोध लेख मौलिक है तथा इसे पूर्व में किसी अन्य पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया गया है।

संदर्भ सूची

- गोविन्दा, आर., एवं बंद्योपाध्याय, एम. (2011). भारत में प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच: देशीय विश्लेषणात्मक समीक्षा. नई दिल्ली, भारत: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA)।

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

- डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन (DISE). (2017). भारत में स्कूली शिक्षा: सांख्यिकी एवं संकेतक. नई दिल्ली, भारत: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA)।
- तिलक, जे. बी. जी. (2007). शिक्षा, असमानता और विकास. नई दिल्ली, भारत: रावत पब्लिकेशन्स।
- द्रेज़, जे., एवं सेन, ए. (2013). एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स. नई दिल्ली, भारत: पेंगुइन बुक्स।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD). (2018). शिक्षा संबंधी सांख्यिकी: एक दृष्टि. नई दिल्ली, भारत: भारत सरकार।
- यूनेस्को. (2015). सभी के लिए शिक्षा 2000–2015: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ. पेरिस, फ्रांस: यूनेस्को पब्लिशिंग।
- सिंह, आर. (2025). ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक: बिहार के नालंदा जिले से साक्ष्य. जर्नल ऑफ़ रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, 12(1), 45–62।